



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32 ]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2002/फाल्गुन 8, 1923

No. 32]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2002/PHALGUNA 8, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2002

सं. टीएएमपी/67/2001-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, संलग्न आदेशानुसार चेन्नई पत्तन न्यास के लौह अयस्क की दरों में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित मामले को बंद करता है।

अनुसूची

मामला सं० टीएएमपी/67/2001- सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

आवेदक

आदेश

(25 फरवरी, 2002 को पारित)

यह मामला सीएचपीटी से लौह अयस्क प्रहस्तन कार्य की दरों के संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. सीएचपीटी ने लौह अयस्क प्रहस्तन कार्य में हुए घाटे को पूरा करने के लिए इस कार्य की दरों में 125%

तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। उसने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही हैं :-

- (i) प्राधिकरण ने अपने 22 मार्च, 2000 के सामान्य संशोधन आदेश में लौह अयस्क प्रहस्तन कार्य के लिए प्रशुल्क दरों में उसके द्वारा प्रस्तावित 100% वृद्धि के बजाय 40% की वृद्धि का अनुमोदन किया था। उसके द्वारा प्रस्तावित वृद्धि इस कार्य के लागत विवरण पर आधारित थी जिसमें वर्ष 1995-96 से 20/-करोड़ रु० से अधिक का घाटा निरंतर दिखाया गया था।
- (ii) उपर्युक्त सामान्य आदेश में प्राधिकरण ने पीओएल और कंटेनर प्रहस्तन कार्यों के लिए किसी वृद्धि को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया था कि ये कार्य अतिरिक्त थे। साथ ही उसके द्वारा लौह अयस्क प्रहस्तन कार्य में घाटे को पूरा करने के लिए प्रस्तावित 100% की वृद्धि को भी स्वीकार नहीं किया गया।
- (iii) प्राधिकरण द्वारा 10 अप्रैल, 2000 से 40% की वृद्धि को अनुमोदित किए जाने के बावजूद वर्ष 2000-01 में इस कार्य में 42.21/- करोड़ रु० का घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001-02 में 55 करोड़ रु० का और वर्ष 2002-03 71 करोड़ रु० का घाटा होने का अनुमान है।
- (iv) कोयला प्रहस्तन के कार्य को सीएचपीटी से एनोर पत्तन में अंतरित करने के कारण राजस्व में और भी हानि होने की संभावना है।
- (v) सचिव (नौवहन) ने नई दिल्ली में 7 जून, 2001 को पत्तन अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में सीएचपीटी से संबंधित एजेंडा की एक मद में यह निर्णय किया कि पत्तन लौह अयस्क दरों को संशोधित करने के लिए समुचित कार्रवाई कर सकता है।
- (vi) इस परिप्रेक्ष्य में उसने लौह अयस्क प्रहस्तन कार्य की दरों में 125% तक की वृद्धि करने के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन मांगा है।

3 निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के अनुपालन में सीएचपीटी का प्रस्ताव संबंधित पत्तन प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं को उनकी टिप्पणी के लिए परिचालित किया गया। विभिन्न पत्तन प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं से प्राप्त टिप्पणियाँ सीएचपीटी को उसकी जानकारी/ टिप्पणियों के लिए भेजी गईं। विभिन्न प्रयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों पर सीएचपीटी के अभिमत अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.1 सीएचपीटी ने प्रारंभ में अपने प्रस्ताव के समर्थन में लौह अयस्क कार्य का लागत विवरण प्रस्तुत किया था। परंतु प्रस्तुत लागत विवरण इस प्राधिकरण द्वारा विहित प्रोफार्मा में नहीं था। अतः सीएचपीटी से अनुरोध किया गया कि वह विहित फार्मेट में लागत विवरण पुनः प्रस्तुत करें।

4.2 सीएचपीटी के पिछले सामान्य संशोधन में चूंकि अतिरिक्त कार्यों के लिए दरों को कम नहीं किया गया था अतः घाटे वाले कार्यों की दरों में प्रतिशत वृद्धि के लिए उस समय प्रचलित स्तर पर प्रति सम्मिन्धी जारी रखने का

निर्णय लिया गया था। ऐसी स्थिति में लौह अयस्क कार्य से संबंधित लागत विवरण में हालांकि 148% का औसत घाटा दिखाया गया था परंतु उस समय इस प्राधिकरण ने केवल 40% की वृद्धि की ही अनुमति दी थी। इस मामले में स्वीकार्य प्रशुल्क वृद्धि की मात्रा का निर्णय करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि अन्य कार्यों से लौह अयस्क प्रहस्तन कार्य में अंतर्गत प्रति सप्तिह का अभिनिर्धारण एवं मात्रा निर्धारण किया जाए। इस विश्लेषण का महत्व सीएचपीटी में कंटेनर प्रहस्तन कार्य के निजीकरण के आलोक में और भी बढ़ जाता है। अतः सीएचपीटी से अनुरोध किया गया कि वह पूरे पत्तन के लिए और कार्यों संबंधी समस्त कार्य के लिए लागत विवरण निर्धारित फार्मेट में पुनः प्रस्तुत करें।

5. सीएचपीटी को पुनः हमारे 27 सितंबर, 2000 और अक्टूबर, 2001 के पत्र द्वारा अपेक्षित लागत विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मरण कराया गया। बाद में सीएचपीटी ने वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के सभी कार्यों के लागत विवरण प्रस्तुत किए परंतु ये विवरण भी इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विहित प्रोफार्मा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त सीएचपीटी द्वारा प्रस्तुत सूचना में अगले दो वर्षों के लागत अनुमान भी शामिल नहीं किए गए थे। चूंकि आम तौर पर दो वर्ष का प्रशुल्क चक्र स्वीकृत होता है अतः प्रशुल्क वृद्धि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए अगले दो वर्ष के अनुमान भी अनिवार्य होते हैं। अतः हमारे 8 नवंबर, 2001 के पत्र द्वारा और 21 दिसंबर 2001 तथा 17 जनवरी, 2002 के अनुस्मारकों द्वारा सीएचपीटी से लागत विवरण विहित फार्मेट में प्रस्तुत करने का पुनः अनुरोध किया गया।

6.1 इस मामले में 18 दिसंबर, 2001 को संयुक्त सुनवाई की गई। संयुक्त सुनवाई में सीएचपीटी अपेक्षित लागत विवरण तीन-चार दिनों में प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गया। कई अनुस्मारक दिए जाने और सीएचपीटी द्वारा संयुक्त सुनवाई में पूरा आश्वासन दिए जाने के बावजूद सीएचपीटी ने अभी तक अपेक्षित लागत विवरण विहित प्रोफार्मा में प्रस्तुत नहीं किया है।

6.2 संयुक्त सुनवाई में सीएचपीटी 10 जनवरी, 2002 तक प्रयोक्ताओं के साथ उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए बैठक आयोजित करने के लिए भी सहमत हो गया। सीएचपीटी ने विभिन्न अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद अभी तक इस बैठक के परिणामों की जानकारी नहीं दी है।

71. लागत विवरणों के विहित प्रोफार्मा में प्राप्त न होने के कारण विभिन्न लागत मदों की उपयुक्तता का आकलन करने और प्रति सप्तिह को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के बाद लौह अयस्क प्रहस्तन कार्य के लिए प्रशुल्क में वृद्धि करने के बारे में निर्णय करना संभव नहीं है। अगस्त, 2001 से ही सीएचपीटी से विवरण मांगा जा रहा है; और लगभग 6 माह बीत जाने के बावजूद सीएचपीटी से कोई सार्थक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

7.2 यह प्रस्ताव चूंकि 'प्रशुल्क' मामले के रूप में प्राप्त हुआ है अतः इसे अनिश्चित काल तक लंबित रखना वांछनीय नहीं है। अपेक्षित सूचना चूंकि हमारे द्वारा बार-बार मांगे जाने के बावजूद अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अतः इस मामले को 'बंद' समझना अनिवार्य हो जाता है। इस मामले को बंद करने से पहले यह निर्णय किया गया था कि सीएचपीटी को अपेक्षित लागत विवरण प्रस्तुत करने और प्रयोक्ताओं के साथ हुई बैठक के परिणामों की जानकारी देने का एक और अंतिम अवसर दिया जाए। तदनुसार सीएचपीटी को सूचित किया गया कि यदि अपेक्षित विवरण 22 फरवरी, 2002 तक प्राप्त नहीं हुए तो इस मामले को बंद कर दिया जाएगा। परंतु सीएचपीटी ने अभी तक अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

8.1 उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखकर और सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण विश्लेषण के लिए अपेक्षित सूचना न मिल पाने से इस मामले को बंद करने का निर्णय करता है।

8.2 उल्लेखनीय है कि सीएचपीटी के प्रशुल्कों पर सामान्य पुनर्विचार/संशोधन अप्रैल, 2002 में किया जाना नियत है और लौह अयस्क प्रहस्तन शुल्क से संबंधित स्थिति पर भी उस समय पुनर्विचार हेतु विचार किया जा सकता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/असाधारण/2002]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2002

No. TAMP/67/2001-CHPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby closes the case relating to a proposal of the Chennai Port Trust for revision of rates for handling of iron ore as in the Order appended hereto.

### SCHEDULE

#### Case No. TAMP/67/2001-CHPT

The Chennai Port Trust (CHPT)

---

Applicant

### ORDER

(Passed on this 25th day of February 2002)

This case relates to a proposal received from the CHPT for revision of rates for iron handling activity.

2. The CHPT has proposed to increase the rates for iron ore handling activity by 125% to compensate the deficit in this activity. It has made the following main points in its proposal:

- (i). The Authority had approved a tariff increase of 40% for the iron ore handling activity in its general revision Order dated 22 March 2000 as against the 100%

increase proposed by it. The increase proposed by it was based on the cost statement for this activity which depicted a continuous deficit of more than Rs. 20/- crores from the year 1995-96 onwards.

- (ii). In the said general revision Order, the Authority did not allow any increase for the POL and Container handling activities on the ground that these activities were in surplus. At the same time, the increase of 100% sought by it to absorb the deficit in the iron ore handling activity was also not allowed.
- (iii). In spite of the 40% increase approved by the Authority with effect from 10 April 2000, this activity incurred a deficit of Rs. 42.21/- crores for the year 2000-01. A further deficit of Rs. 55 crores and Rs. 71 crores is estimated in the years 2001-02 and 2002-03.
- (iv). A further loss of revenue is expected due to shifting of coal handling from the CHPT to the Ennore Port.
- (v). The Secretary (Shipping) at a meeting held with the Port Chairmen on 7 June 2001 in New Delhi in one of the agenda items relating to the CHPT decided that the port may take appropriate action to revise the iron ore rates.
- (vi). In this backdrop it has sought the approval of the Authority to increase the rates for iron ore handling activity by 125%.

3. In accordance with the consultation procedure prescribed, the CHPT proposal was circulated to the concerned port users / representative bodies of port users for their comments. Comments received from various port users / representative bodies of port users were forwarded to the CHPT for its information / comments. The views of the CHPT on the comments received from various users is still awaited.

4.1. The CHPT initially furnished cost statement for iron ore activity in support of its proposal. The cost statement furnished was, however, not in the proforma prescribed by this Authority. The CHPT was therefore, requested to resubmit the cost statement in the format prescribed.

4.2. In the last general revision Order of the CHPT, since the rates for the surplus activities were not reduced, percentage increases in the rates for the deficit activities had been decided allowing the incidence of cross-subsidisation to continue at the level existing at that point of time. That being so, though the cost statement pertaining to iron ore activity depicted an average deficit of 148% only 40% increase was then allowed by this Authority. In order to decide on the quantum of tariff increase to be allowed in the instant case, it becomes essential to recognise and quantify the cross-subsidisation flowing from other activities to iron-ore handling activity. This analysis assumes more significance in the wake of privatisation of container handling activity at the CHPT. The CHPT was, therefore, requested to furnish cost statements for the Port as a whole and all cargo related activity in the format prescribed.

5. The CHPT was again reminded to furnish the requisite cost statements vide our letter dated 27 September 2001 and 30 October 2001. Subsequently, the CHPT submitted cost statements for all the activities for the year 1999-2000 and 2000-01 which were again not in the proforma prescribed by this Authority for submission of tariff revision proposals. Further, the information furnished by the CHPT did not contain estimates relating to the next two years. Since a tariff cycle of two years is generally allowed, the estimates for the next two years are essential to decide on the quantum of tariff increase. The CHPT was, therefore, again requested to furnish the cost statements in the format prescribed vide our letter dated 8 November 2001 followed by reminders dated 21 December 2001 and 17 January 2002.

6.1. A joint hearing in this case was held on 18 December 2001. At the joint hearing, the CHPT agreed to furnish the requisite cost statements within three to four days. Despite several reminders and its emphatic assurance made at the joint hearing, the CHPT has not yet furnished the requisite cost statements in the prescribed proforma.

6.2. At the joint hearing, the CHPT also agreed to arrange an interactive meeting with the users by 10 January 2002 to clarify different issues raised by them. The CHPT has not yet intimated the outcome of this meeting, despite a reminder issued.

7.1. In the absence of the cost statements in the prescribed proforma it is not possible to decide on the increase in tariffs to be allowed for the iron ore handling activity after assessing the reasonableness of various cost items and reckoning with the flow of cross-subsidies at the existing level. The details have been requisitioned from the CHPT since August 2001; and, even after a lapse of nearly 6 months no meaningful response has been received from the CHPT.

7.2. Since the proposal is received as a 'tariff' case, it is not desirable to keep it pending indefinitely. As the requisite information is not forthcoming despite our continuous efforts to obtain them, it has become unavoidable to treat this case as 'closed'. Before closing the case, it was decided to give a final opportunity to the CHPT to furnish the requisite cost statements and intimate the outcome of the interactive meetings with the users. The CHPT was accordingly, informed that if the requisite details were not received by 22 February 2002, the case would be closed. The CHPT has not yet furnished the requisite information.

8.1. In the light of the position explained above, and based on a collective application of mind, this Authority decides to close this case for want of information required for analysing it.

8.2. It is noteworthy that the general review / revision of the CHPT tariffs falls due in April 2002 and the position relating to iron-ore handling charges can be taken up for review then.

S. SATHYAM, Chairman

[No. ADVT/III/IV/143/Exty/2002]